

Roll No.

LM-102/LM-1002

The Indian Constitution Law : The New Challenge

(भारतीय संवैधानिक विधि : नवीन चुनौतियाँ)

Master of Law (LLM-11/12/16)

First Year, Examination, 2017

Time : 3 Hours

Max. Marks : 70

Note : This paper is of **seventy (70)** marks containing **three (3)** sections A, B, and C. Learners are required to attempt the questions contained in these sections according to the detailed instructions given therein.

नोट : यह प्रश्न पत्र सत्तर (70) अंकों का है जो तीन (03) खण्डों 'क', 'ख' तथा 'ग' में विभाजित है। शिक्षार्थियों को इन खण्डों में दिए गए विस्तृत निर्देशों के अनुसार ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

Section-A / खण्ड-क

(Long Answer Type Questions) / (दीर्घ उत्तरीय प्रश्न)

Note : Section 'A' contains four (04) long answer type questions of fifteen (15) marks each. Learners are required to answer *two* (02) questions only.

नोट : खण्ड 'क' में चार (04) दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिये गये हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए पन्द्रह (15) अंक निर्धारित हैं। शिक्षार्थियों को इनमें से केवल दो (02) प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

1. Point out the need for and kinds of grant, given by the union of India to different states. Does the Finance Commission play any role in giving grants-in-aid ?

भारत संघ द्वारा विभिन्न राज्यों को दिये जाने वाले अनुदानों की आवश्यकता और प्रकार बताइए। क्या अनुदान की सहायता देने में वित्त आयोग की कोई भूमिका है ?

2. Do Judges appoint Judges in India ? Discuss. Also point out the directions given by the Supreme Court in this respect in Supreme Court Advocates on Record Assn. vs union of India, A. I. R. 2016, S. C. 117.

क्या भारत में न्यायाधीश ही न्यायाधीशों को नियुक्त करते हैं ? विवेचना कीजिए। उच्चतम न्यायालय द्वारा सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसो. बनाम भारत संघ, ए. आई. आर. 2016, सु. को. 117 में दिये निर्देशों पर भी प्रकाश डालिए।

3. Point out the various fundamental duties contained in Article 51-A of the constitution and their significance. Can any of such duty be enforced by a Court of law ?

Parliament enacted a law under Art. 51-A (g) of the constitution for protection of forests. Can this law be enforced by a Court ? Give reasons.

संविधान के अनुच्छेद 51-क में उल्लिखित विभिन्न मूल कर्तव्यों को बताइए और उनके महत्व पर प्रकाश डालिए। क्या ऐसा कोई कर्तव्य न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है ?

संसद में वनों की सुरक्षा के लिए संविधान के अनुच्छेद 51-क (छ) के अनुसार एक कानून बनाया है। क्या इस कानून को न्यायालय प्रवर्तित कर सकता है ? सकारण उत्तर दीजिए।

4. Write a critical note on corruption in public life and measures to contain it. How far political corruption has affected Indian economy ?

लोक जीवन में भ्रष्टाचार तथा इसको रोकने के उपायों पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए। राजनैतिक भ्रष्टाचार ने भारत की अर्थव्यवस्था को कितना प्रभावित किया है ?

Section-B / खण्ड-ख

(Short Answer Type Questions) / (लघु उत्तरीय प्रश्न)

Note : Section 'B' contains eight (08) short answer type questions of five (05) marks each. Learners are required to answer *six* (06) questions only.

नोट : खण्ड 'ख' में आठ (08) लघु उत्तरीय प्रश्न दिये गये हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए पाँच (5) अंक निर्धारित हैं। शिक्षार्थियों को इनमें से केवल छः (06) प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

1. Point out the basic difference between Art. 356 and Art. 365 of the Constitution.
संविधान के अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 365 में मूल अन्तर स्पष्ट कीजिए।
2. Write a note on statutory regulation of press and electronic media under Art. 19(1)(a) of the Constitution.
संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के अधीन प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विधिक विनियमन पर टिप्पणी लिखिए।
3. Which States are included for which special provisions exist for administration of Tribal Areas ? Discuss Constitution of a District Council.

उन राज्यों का उल्लेख कीजिए जिनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए व्यवस्था है। जिला परिषद् के गठन पर प्रकाश डालिए।

4. Sum up the articles which deal with right to equality under the Constitution of India.

भारत के संविधान के उन अनुच्छेदों का सारांश बताइए जो समता के अधिकार से सम्बन्धित हैं।

5. Distinguish between Judicial activism and judicial obstinacy.

न्यायिक सक्रियता और न्यायिक हठ में अन्तर बताइए।

6. Explain Public Interest Litigation with the help of any leading case.

किसी अग्र निर्णय की सहायता से लोक हित वादकारिता को समझाइए।

7. With the help of case law point out on to how 'minority' is determined for the purposes of Article 29 and 30 of the constitution.

संविधान के अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 के लिए 'अल्पसंख्यक' का निर्धारण करने का तरीका निर्णयज विधि के आधार पर बताइए।

8. Write a critical note on executive accountability.

कार्यपालिका के उत्तरदायित्व पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए।

Section-C / खण्ड-ग**(Objective Type Questions) / (वस्तुनिष्ठ प्रश्न)**

Note : Section 'C' contains ten (10) objective type questions of one (01) mark each. All the questions of this section are compulsory.

नोट : खण्ड 'ग' में दस (10) वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिये गये हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक (01) अंक निर्धारित है। इस खण्ड के सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

Fill in the blanks :

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :

1. As on 31 March, 2016, the Supreme Court of India consists of Judges.

31 मार्च, 2016 को भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश है।

2. Every High Court is to the Supreme Court of India.

प्रत्येक उच्च न्यायालय भारत के उच्चतम न्यायालय के हैं।

3. The Comptroller and Auditor General of India can be removed on the grounds of

भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक को के आधार पर पद से हटाया जा सकता है।

4. Article 300-A of the Constitution deals with the right to

संविधान का अनुच्छेद 300 'क' के अधिकार से सम्बन्धित है।

5. The first amendment of the Constitution was made by

संविधान का प्रथम संशोधन ने किया था।

6. Article 323 A was inserted by the Constitution Amendment Act.

अनुच्छेद 323 'क' संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अन्तःस्थापित किया गया था।

7. T.M.A. Pai Foundation vs. State of Karnataka, A. I. R. 2003, S. C. 355 was decided by a Bench of J. J.

टी. एम. ए. पाई फाउण्डेशन बनाम कर्नाटक राज्य, ए. आई. आर. 2003, एस. सी. 355 का निर्णय न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने किया था।

8. Keshavanand Bharti vs. State of Kerala, A. I. R. 1973, S. C. 1641 was decided by a majority of Judges.

केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य, ए. आई. आर. 1973, एस. सी. 1641 का निर्णय न्यायाधीशों के बहुमत से हुआ था।

9. The power of President under Art. 356 is really that of

राष्ट्रपति की अनुच्छेद 356 की शक्ति वास्तव में की शक्ति है।

10. The Constitution of India has been amended times till 2015.

भारत के संविधान में 2015 तक संशोधन किये गये हैं।